(ii) Eighth Report on the Action Taken by the Government on the Recommendations / observations contained in the Seventeenth Report of the Committee on the subject of "Edible Oils"

RE: GREVANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभापति महोदया....

उपसभापति: आप किस पर बोल रहे हैं?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सदन के अधिवेशन का अंतिम दिन है और लगातार पिछले 10-15 दिन से हम यह बात उठा रहे हैं। आपने इस संबंध में डायरेक्शन भी दिया था, हम मैंबर्स के गैस के कूपन और टेलीफोन के कनक्शन के बारे में यहां कह रहे हैं। मंत्री जी ने यहां सदन में आश्वासन भी दिया था, आपने इस बारे में निर्णय किया, बिज़िनस ऐडवाइज़री कमेटी ने निर्णय किया और सब कुछ होने के बाद भी आज अंतिम दिन है, डेढ़ महीना बीत गया है। उपसभापति महोदया, इसमें किसी का पर्सनल फायदा नहीं है, गरीब आदमी को मिलने वाला टेलीफोन और गरीब आदमी को मिलने वाला गैस का कोटा है। इसमें चार हजार रुपये आपने गैस के कूपन की फीस कर दी और यह कह दिया कि चार हजार रुपये दें तो उसको गैस मिलेगा। टेलीफोन की तीस हजार रुपये फीस कर दी। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो मैंबर्स के थ्रू गरीब आदमी को मिलने वाली एक सुविधा थी जिसको मैंबर अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में दे सकता था परन्तु इसमें लगातार इतने दिन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं करती, कोई निर्णय नहीं करती। इसके कारण यह हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जबकि आपका डायरैक्शन आ चुका है तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में सदन की राय लेकर आप सरकार को डायरैक्ट करें कि इसको फौरी तौर पर लागू करें नहीं तो आज सब लोग चले जाएंगे तो फिर यह कोटा उनको कैसे मिलेगा और कब प्राप्त होगा? ...(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): मैडम, यह विषय कई बार उठ चुका है आसन से भी निर्देश दिया जा चुका है यह समझ में नहीं आता कि आखिरी दिन है, आज के बाद मैंबर्स चले जाएंगे। तो अब तक सरकार का राज्य सभा के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ। मंत्री महोदय यहां कह चुके हैं। समझ में नहीं आता कि यह सरकार क्या कर रही है। यह सरकार हर मामले में अपना हाथ पीछे खींच रही है। क्या गैस का कूपन हमें अपने लिए चाहिए? मेरा मेकेनिक है, ड्राइवर है, नौकर है, कांस्टीट्यूऐसी में हमारे वर्कर्स हैं उनको कमिटमेंट किए हुए हैं। अगर आपको यह बंद भी करना था तो चार-छः महीने का नोटिस आपको देना चाहिए था। According to the principle of natural justice, we have committed to so many people that we will give them in the April quota. Now, a long list is pending with us. We are maintaining registers, but how do we meet them and how do we face them? After all, if somebody has made some *gadbadi* somewhere, you take him to task. It doesn't mean that it should be given up. The Government is committed to giving it. It must be given to us today itself.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): मैडम, अगर इन चीजों का कोई मिसयूज़ कर रहा है तो वह हाउस को मालूम होना चाहिए। कोई भी मैंबर अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में इनका प्रॉपर यूज़ कर रहा है, चाहे वह टेलीफोन हो या गैस कनक्शन हो, उनके वर्कर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको मानने वाले होते हैं, ऐसे तमाम लोग आज डेढ़ महीने से परेशान हैं। न हम किसी को कोई गैस कनक्शन दे पाए हैं, न टेलीफोन दे पाए हैं। जो इसका मिसयूज़ कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए पर इसके लिए सारे मैंबर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। (व्यवधान)...

श्री राघव जी (मध्य प्रदेश): महोदय, सदन को सूचना नहीं दी गयी है। ...(व्यवधान)... यह पता नहीं चलता है कि कब से हो रहा है? ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): It has been decided that it would be raised to 1,00,000 but that is not done. We cannot afford to run the show like this.

श्री वसीम अहमद: अगर कोई मिसयूज़ करता है तो ...(व्यवधान)...

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): The thing is that it has never been announced in this House that the decision taken there will be applicable to the Members

of this House. As my colleague has said if it has been stopped as a policy after an agreement between the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha, then, at least there should be an advance notice so that our earlier commitments can be met.

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला (पंजाब): मैडम मैं आपका आभारी हूं। श्री मल्होत्रा जी ने जो सवाल गैस कनक्शन और टेलीफोन का उठाया है, वह बिल्कुल सही है। अगर आप इसको ऐक्जामिन कराएं तो आप पाएंगे कि गरीब आदमी को वह गैस हम देते हैं। हम उसे अपने लिए नहीं मांग रहे है यह हम गरीब लोगो के लिए मांग रहे हैं जिनको हम गैस कनक्शन देते हैं, टेलीफोन देते हैं। आपकी डारेक्शन इस संबंध में ऑलरेडी हैं, आपको सिर्फ उसको इम्लीमेंट करवाना है। दूसरा यह है कि कुछ फैसेलिटीज़ है, खासकर टेलीफोन कॉल्स का 50,000 से लाख तक और तनख्वाह, इस संबंध में भी हाऊस में प्रॉमिस किया हुआ है, उसको भी जल्दी टेकअप करना चाहिए। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप सरकार को दुबारा बताइए। यह सरकार अभी भी जगाने वाली नहीं है, यह कम जागती है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको डायरेक्शन दीजिए और यह काम करवाइए क्योंकि आज आखिरी दिन है।

श्री राधकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश): मैडम मैं केवल आधा मिनट लूंगा। आज उपराष्ट्रपति की सेलरी वाला बिल आ रहा है। तो मैंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहुत कम सैलरी मिलती है, इससे ज्यादा तो हमारे स्टेट के एम० एल० ए० को मिलती है। जब पूरा हाउस उस पर एग्री है तो मेहरबानी करके एमपीज की सेलरी वाला बिल भी लाया जाये और मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए टेलीफोन गैस कनेक्शन की सुविधा होनी चाहिए।

उपसभापति: हां, आप बोलिए।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, it is very sad that Members of Parliament ...(*Interruptions*). I want to say something to this House and through you, to the Government. India has some of the largest constituencies. Some of the Members represent what are small nations elsewhere. We actually look after millions of people. It is physically impossible and fiscally impossible to run this in this way. And we have to beg for these things. These are not privileges. There are necessities. We do not mind not getting telephones. But places take the responsibility to tell the petitioner who comes to us. वह घर पर आकर बैठ जाते हैं कि आप टेलीफोन पर मंत्री जी से बात कर लीजिए। इसका भी तो कोई हिसाब रखिएगा कि इसमें कितने पैसे लगते हैं। फिर भी, लोग हमारी तरफ उंगुली उठाते हैं कि मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को यह चाहिए और वह चाहिए। हम एमएलए से ज्यादा कुछ नहीं लेते हैं, हमको एमएलए से कम ही मिलता है। यह शर्म की बात है।

श्री गोविन्द राम मिरी: (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश के एमएलएं को एमपी से ज्यादा मिलता है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: एमएलए की सात कांस्टीटुअंसी से लोक सभा की एक सीट बनती है और राज्य सभा के सदस्य को तो पूरी स्टेट की ही देखभाल करनी होती है। लोग बाहर ऐसी बाते करते हैं जैसे कि हम कोई लूट मचा रहे हैं। हमारी भी कुछ जरूरतें होती है। हमारे घर पर पिटिश्नर आते हैं। वे जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं सीधे ही बोरिया-बिस्तर लेकर के घर पर आ जाते हैं। उनमें से कोई कहता है कि हमारे हाथ-पांव टूटे है हमें अस्पताल में दाखिल करवा दीजिए, कोई कहता है कि दिल का आपरेशन करवा दीजिए और किसी का अन्य कोई कार्य होता है। यह कौन सी परिस्थिति आई है कि हम लोगों को हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है। It is a shameful situation that we are not taking congnizance of the reality. हम ऐसे कौन सें करोड़ों रुपये की मांग कर रहे हैं। जो लोग इस हाउस में आते हैं वे सभी पैसे वाले नहीं होते हैं। यहां पर डेमोक्रेसी है इसलिए कई लोग यहां तक आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। यह हमारी किस्मत का खेल है। हमारे पीछे तो कोई बैंक अकाउन्ट नहीं है जिससे हमारी देखभाल हो सके। आप मेंबर्स को मजबूर कर रहे हैं। to feel ashamed to talk like this, Madam, through you I wish to convey this. *(Interruptions)*.

SHRI R. K. KUMAR (Tamil Nadu): I fully and strongly support all the demands *(Interruptions)*.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): मैडम, हमारी बहिन रेणुका जी ने जो कहा और लोगों ने जो कहा उसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बात सही है कि अभी-अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्पलाइज के लिए पे-कमीशन की रिपोर्ट आई है। आपने उसमें देखा होगा कि आफीसर्स की तनख्वाह 25-26 हजार हो गई है लेकिन एमपीज की तनख्वाह 1500 रुपये है। इस समय एक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह 1500 रुपये है और पे-कमीशन ने एक आफीसर की तनख्वाह 26,000 रुपये रिकमण्ड कर दी है। हमारे लिए तनख्वाह बढ़ाने की रिकमडेशन तो आप ही कर सकती हैं और ये चेयर की ओर से होगा। अगर हमारी तनख्वाह और हमारा डेली अलाउंस बढ़ जाता है तो सारी दुनिया में कोहराम

मच जाता है, लेकिन हम क्या करें, यह बता दीजिए To discharge the duties of a Member of Parliament effectively, what should we do? How do we do it? यह बात सही है कि मेंबर्स आॅफ पार्लियामेंट वह चाहे राज्य सभा के हों या चाहे लोक सभा के हो, उनके घर पर लोग आते हैं, उनसे काम करवाने की अपेक्षा करते हैं जिसके लिए हजारों फोन मेंबर्स को करने पड़ते हैं, हजारों चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। एक-एक चिट्ठी के लिए भी हमें कागज खरीदना पड़ता है, एक-एक लिफाफा भी हमें खरीदना पड़ता है। On everything we have to spend. Where do we get the money from? आप या तो अलग-अलग सभी एमपी के लिए बिजनिस खुलवा दीजिए, जिससे कि उन्हें हर महीने 10-20 हजार रुपये की आमदनी हो सके।...

उपसभापति: चव्हाण साहब आप भी बोल दीजिए (व्यवधान)...

श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला: ये हमें कहते हैं कि आप इसे रेज करिए। ...(व्यवधान)...

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, I would......

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not want to continue the discussion on this.

SHRI M. A. BABY: Madam, I want just half of a minute of induglence because it has been raised by our hon. Colleauge.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not want to continue this. *(Interruptions)*. Just one second.

SHRI M. A. BABY: We have our serious reservations about increasing the salary *(Interruptions)*.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I do not want to stand and beg for anything. I am asking for what are my rights, what are my fundamental needs, what are my privileges and what I am entitled to. I am tired of this game ...*(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Enough is enough. Please sit down. *(Interruptions)*.

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Madam, it is very unfortunate that I have to bring one fact to the notice of the hon. House. Most of the Members of the Communist Party requests to raise this matter on the floor of the House and they will support us. But now they are saying something else. *(Interruptions)*. It cannot go on like this. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Singla, you made your point. Will you please sit down?

SHRI M. A. BABY: Madam, may I have your indulgence? This is an allegation. I want to put the record straight. I have great respect for Singla Ji. He said that some of the Members of the Communist Party requested him that they cannot raise this matter and he has to raise it. In that case, I would like to know which Member has requested him. We want to know. It is not our position. I want to put it on record.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let me put the record straight. There is a Committee of both the Houses of Parliament, represented by all the political parties which goes into the details about emoluments and privileges of the Members regarding telephones, airline tickets etc. etc. That Committee is represented by all political parties from both the Houses of Parliament. That Committee sat, discussed and made certain recommendations to the Speaker long back. The Committee gave it recommendations twice. Those recommendations are before the Government. Everybody is committed to it. So, please don't create any kind of feeling that half of the Members are for it and half of the Members are against it because everybody is represented in that Committee. So, the matter is before the Government. I would request the representative of the Government to listen to the grievances of the Members and take appropriate action as per the recommendations of the Committee of both the Houses of Parliament. *(Interruptions)*. That matter is over now.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra):

Madam, I would like to submit a small point for your consideration. All these aspects were thoroughly gone into. You have given your direction. Now the question is: "Why is the Government not responding?" Certainly, we are entitled to know as to why the Government is keeping mum. They are not responding to anything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Venkatraman, if you represent the Government, please respond.

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): Madam, I can only pass on the information. *(Interruptions).* I have heard the sentiments expressed by the hon. Members and I will pass on the information to the quarter concerned. *(Interruptions).*

SHRI SATISH AGARWAL: Are you a Minister or a postman that you will pass on the information?*(Interruptions).*

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: It is the collective responsibility of the Government. *(Interruptions).*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't make an issue like this. Don't make an issue in that manner; it looks unruly. The Government is seized of the situation. Mr. Minister, please don't say that you will convey the feelings of the Members. Fine. You are conveying the information. The House appreciates it. But there is a two-way system. When the Members raise an issue on the last day, while you convey, you convey the reaction of the Government back to the Members.

SHRI T. G. VENKATRAMAN: I will certainly convey the feelings of the Members that the matter should be decided.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whatever may be the views of the Government, it should be communicated. *(Interruptions).*

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam, I would like to submit one point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more discussion on this subject.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: I am not going to say anything on this topic. I am going to say something else. Madam, I have to draw the attention of the House to your earlier rulings that at least either the Minister of Parliamentary Affaris or the State Minister should be present here. Somehow or the other, it has been happening for the last few days that neither the Minister for Parliamentary Affairs nor the State Minister is present in the House. This is rather very unfortunate. And it is through the Minister of State for Parliamentary Affairs that we normally conduct such business.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The thing is that Ministers are here. but the Parliamentary Affairs Minister are specially responsible for the Parliamentary work. Mr. Venkateswarlu had got some business in the other House. So, he had to leave, but I am sure, he could have been substituted by someone else. I will ask somebody to take the responsibility because it is their duty to ensure communication betweem the Government and the House. Mr. Venkatraman, now you are taking the responsibility, fine. I appreciate it, but the Member wishes that the one who is assigned for it, should also be there.

RE. ATROCITIES COMMITTED ON MINORITIES

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, आज सदन उठने के बाद यह नहीं मालूम हम सब कब बैठेंगे। आज़ादी के 50 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी खुशियां भी हमारे देश में मनाई जानी है लेकिन इन 50 सालों में हमने जितने साल गुज़ारे हैं, उन सालों में हर साल कोई नया सवाल हमारे सामने आया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) पीठासीन हुए]

यह साल इसलिए भी ज्यादा हमारे लिए सोचने का